लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16 - 31 जनवरी, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक -58

“प्रकृति ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। यहां कोई पराया नहीं है, पृथ्वी से आकाश तक सब अपने हैं।

: मधुकर

डिजिटल कामकाज से मिली विकास को रफ़्तार 4

सरस मेले में जुटे हस्तशिल्प के कद्रदान 7

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 8

पंचायती संस्थाओं की बढ़ी 'ताकत'

ग्रामीण व शहरी विकास के लिए अब खुद खर्च कर सकेंगी बजट

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायतता प्रदान की है। पूर्व की भांति पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-एड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के कार्य होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ही होगी। उदाहरणतः 2 लाख रुपए के कार्य हों या 2.50 करोड़ रुपए के, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति सरपंच तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा उनके अपने स्तर पर ही दी जाएगी। पहले प्रशासनिक स्वीकृति के लिए फाइलें राज्य सरकार के पास आती-जाती थी। इस कदम से पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत मिलेगी जिससे गांवों में विकास कार्य तेज़ गति से हो सकेंगे।

पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-एड में से होने वाले छोटे या बड़े सभी प्रकार के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा ही दी जाएगी। हालांकि, ऐसे विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के लिए सरकार ने विभिन्न स्लैब निर्धारित की है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा। 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एसडीओ देगा। 25 लाख से एक करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी अभियंता देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षक अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता देगा।

विकास कार्यों के लिए यदि पंचायती राज संस्थाओं के पास राशि कम पड़ती है और उनकी मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त फंड प्रदान करती है, तो उस स्थिति में 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए यह राशि यानी 25 लाख रुपए सीधे पीआरआई को दी जाएगी। 25 लाख रुपए से ज़्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाएंगे। इसके लिए, 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के निदेशक द्वारा दी जाएगी और इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक सचिव तथा तकनीकी स्वीकृति अधीक्षक अभियंता देगा। 2.5 से 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति विकास एवं पंचायत मंत्री द्वारा दी जाएगी और तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

नये कार्यों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से होने वाले मरम्मत और रखरखाव के छोटे या बड़े सभी कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ही मिलेगी। हालांकि, 20 हजार रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा। 20 हजार से 2.50 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एसडीओ देगा। 2.50 लाख से 10 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक्सईएन देगा। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षक अभियंता तथा 25 लाख रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

वरदान साबित होती चिरायु योजना

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'चिरायु हरियाणा योजना' वरदान साबित हो रही है। गंभीर बिमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य कर रही है। जब कभी गरीब परिवार पर किसी बीमारी का संकट आता है तो वह आर्थिक बोझ के कारण और टूट जाता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' की तर्ज़ पर 21 नवंबर , 2022 को 'चिरायु हरियाणा योजना' शुरू की है। इसके तहत सालाना पांच लाख रुपए तक के मुफ़्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। 21 नवंबर, 2022 से अब तक 10,378 लागों को मुफ़्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। इस पर हुए 19 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्च सरकार ने उठाया है ।

चिरायु हरियाणा

केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार 'आयुष्मान भारत योजना' के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक सामाजिक व जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। 'चिरायु हरियाणा योजना' लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में आ गए हैं। अब 28,89,036 परिवार कवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 को 'अंत्योदय आरोग्य वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के दौरान हमारा यही प्रयास है कि हर व्यक्ति निरोगी रहे और बीमार न हो। परंतु फिर भी यदि बीमारी रूपी संकट गरीब परिवारों पर आता है तो वे 'आयुष्मान भारत योजना' तथा 'चिरायु हरियाणा योजना' का लाभ उठाएं।

सरकारी मदद से जीवन सरल हुआ

फरीदाबाद से बिमला ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना चलाकर सरकार ने गरीब परिवारों का कल्याण किया है। उन्होंने बताया कि उनकी बीमारी के इलाज पर लगभग 1एक लाख रुपए का खर्च हुआ, जो सरकार ने वहन किया। अंबाला कैंट से अनिल ने बताया कि उनका लगभग 45 हजार रुपए तक का इलाज का खर्च आया था, लेकिन सरकार की योजना के कारण उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ा, इसके लिए मुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार का धन्यवाद। झज्जर से बिट्टू ने बताया कि उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिस पर भारी भरकम बिल आया लेकिन उनका इलाज मुफ़्त हुआ, इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अन्य लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए यह योजना चलाई है।

44 लाख से ज़्यादा लोगों के बने गोल्डन कार्ड

मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु हरियाणा योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभर्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं।

-संवाद ब्यूरो

1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले आठ वर्षों में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई-भतीजावाद को छोड़कर हरियाणा की राजनैतिक परिभाषा बदलने की पहल करते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान काम करने की कवायद आरंभ कर एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से 1,882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की आधारशिला एवं उद्घाटन कर 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के विज़न को साकार करते हुए प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी है। गुरुग्राम के धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे बजट का 34.5 प्रतिशत हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग का एक निश्चित बजट होता है, हालांकि कभी-कभी वित्त वर्ष के अंत में कुछ विभागों का बजट बच भी जाता है और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी ना आये इसके लिए हमने एक नई पहल करते हुए 'मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिज़र्व फंड' बनाया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास की गई 12 प्रमुख परियोजनाओं में पृथला, पलवल एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रैनीवैल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना, सतनाली खण्ड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र, दिल्ली हिसार रोड, शीला चौक पर ऊपरगामी पुल, रोहतक खरखौदा दिल्ली बॉर्डर रोड पर जेएलएन फीडर और बीएसबी नहर पर स्टील के पुल के कार्य का उद्घाटन तथा भिवानी-हांसी मार्ग का तोशाम बाईपास से जोड़ने वाले रेलवे ऊपरगामी पुल का उद्घाटन शामिल है।

इसके अलावा, राय-मलिकपुर-नांगल चौधरी-नारनौल महेन्द्रगढ़-दादरी चार-मार्गी सड़क के निर्माण, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय हैबिटैट सेंटर, सेक्टर-1, पंचकूला, बड़खल झील के जीर्णोद्धार से संबंधित निर्माण कार्य, झज्जर लिंक ड्रेन को बुर्जी संख्या 5150 से 16500 तक पक्का करने (आर.सी.सी. बाक्स बनाना) व सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास, राजकीय महाविद्यालय, इसराना, पानीपत के भवन का शिलान्यास, करनाल-काछवा-सांभली-कौल सड़क पर समानांतर सतलुज यमुना लिंक नहर व नरवाना ब्रांच नहर के ऊपर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।

जिला महेंद्रगढ़ को करीब 421.42 करोड़ की लागत की तीन परियोजनाएं मिली हैं। जबकि पलवल को 187 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाएं, गुरुग्राम को 168.36 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं तथा फरीदाबाद को 143 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाएं मिली हैं। इसी प्रकार, अंबाला को करीब 15.57 करोड़ के चार प्रोजेक्ट, भिवानी को 31.45 करोड़ के चार प्रोजेक्ट, चरखी दादरी को दो करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं, फतेहाबाद को 2.31 करोड़ रुपए के सात प्रोजेक्ट, हिसार को 5.65 करोड़ की दो परियोजनाएं, झज्जर को 371 करोड़ की लागत की 23 परियोजनाएं तथा जींद को 22.76 करोड़ की लागत की चार परियोजनाओं की सौगात मिली है।

कैथल को 1.19 करोड़ की लागत की एक परियोजना, करनाल को 74 करोड़ की 17 परियोजनाएं, कुरुक्षेत्र को 1.50 करोड़ की लागत की चार परियोजनाएं, नूंह को 37.36 करोड़ की लागत की 12 परियोजनाएं और पंचकूला को 105.67 करोड़ की लागत के तीन प्रोजेक्ट मिले हैं। पानीपत को 76 करोड़ रुपए की लागत के 14 प्रोजेक्ट, रेवाड़ी को 35.42 करोड़ रुपए की लागत के 6 प्रोजेक्ट, रोहतक को 86.40 करोड़ रुपए की लागत की चार परियोजनाएं, सिरसा को 12.24 करोड़ रुपए की लागत के 12 प्रोजेक्ट, सोनीपत को 22.56 करोड़ की लागत की पांच परियोजनाएं तथा यमुनानगर को 57.50 करोड़ की 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है।

संपादकीय

ग्रामोत्थान की ओर नया कदम

गांवों के सशक्तीकरण की दिशा में यह एक अनूठा कदम है। संभवतः हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य है जहां यह बदलाव आने जा रहा है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का सशक्त करने की दिशा में अहम् कदम उठाया है। विकास कार्यों की मंजूरी के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को दो लाख से लेकर ढाई करोड़ रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति देने के अधिकार दिए हैं। गांवों में सरपंच दो लाख तक के काम को 'कोटेशन' के आधार पर ही करवा सकेंगे। वहीं विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों एवं बजट आदि से जुड़ी तकनीकी स्वीकृति के लिए अलग-अलग स्लैब तय किए हैं। जिला परिषद के सीईओ से लेकर विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री तक के स्तर पर अधिकार तय किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर विभाग ने सभी जिलों के डीसी, बीडीपीओ, जिला परिषद के सीईओ, पंचायत अधिकारियों सहित अन्य को अवगत करवाया है।

पूर्व की भांति पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-एड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ही होगी। दो लाख रुपए के काम हों या 2.50 करोड़ रुपए के काम हों, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति सरपंच तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा उनके अपने स्तर पर ही दी जाएगी। पहले प्रशासनिक स्वीकृति के लिए फाइलें राज्य सरकार के पास आती थीं। इन नए फैसलों का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब गांवों के विकास की दिशा में कोई बाधाएं सामने नहीं आ पाएंगी और पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी।

इस कदम से पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत मिलेगी। गांवों में विकास कार्य तेज गति से हो सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-एड में से होने वाले छोटे या बड़े सभी प्रकार के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायतों द्वारा ही दी जाएगी।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

हरियाणा कैबिनेट की बदली तस्वीर

विभागीय कामकाज प्रबंधन के चलते हुए फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल की तस्वीर में भी बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री के पास अब 14 विभाग रहेंगे। जो विभाग किसी को अलॉट नहीं हुए हैं उनका कामकाज भी सीएम के जिम्मे रहेगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हायर एजुकेशन में मिला दिया गया है। यह जिम्मेदारी मंत्री मूलचंद शर्मा की रहेगी। उनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी है। बावल से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, जबकि सीएम ने उनसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग अपने पास रखा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग भी दिया गया है। पंचायत ममंत्री देवेंद्र सिंह के पुरातत्व एवं संग्रहालय को हैरिटेज और पर्यटन में मिलाया गया है। ये विभाग स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास रहेंगे। उनके पास आतिथ्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग यथावत रहेंगे।

'मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल' का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में एक और सादगी का उदाहरण देते हुए अपने विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप दिए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 'मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल' का शुभारम्भ किया गया है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग डा. अमित अग्रवाल ने संत कबीर कुटीर में 'मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल' का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है और इससे मिली धनराशि को 'नमामी गंगे' सफाई अभियान में लगाया है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उपहारों से प्राप्त धनराशि को 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के जरिए उपयोग किया जाए। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग लेने के लिए पांच हजार रुपए की राशि के साथ अपना पंजीकरण कर सकता है।

पोर्टल की शुरुआत हो गई है और यह 28 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद साल में तीन या चार बार पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। पहले चरण में 51 उपहारों की नीलामी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति cmuphaarhry.com पर पंजीकरण करके इन उपहारों की नीलामी में भाग ले सकता है। पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 7087513186 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

लोकसभा की तर्ज़ पर लगा शीतकालीन सत्र

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 से 28 दिसंबर 2022 तक चला। सदन की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज़ पर देखने को मिली। हर सदस्य की सीट पर टैबलेट्स लगे और कार्यवाही का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ लाइव दिखाया गया।

विधानसभा को पेपर लैस किया गया है। विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अध्यक्ष ने ड्रेस कोड लागू किया। तीन दिवसीय सत्र के दौरान 16 विधेयक पारित हुए।

नई पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए नयी व्यवस्था बनाई गई है। पंचायती राज संस्थाओं को जो भी ग्रांट-इन-एड दी जाती है, उसे खर्च करने का अधिकारी इन्हीं संस्थाओं का है, क्योंकि ये स्वायत संस्थान हैं। पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम को भी और अधिक स्वायतता दी जाएगी। अब सरपंच 2 लाख तक के कार्य कोटेशन आधार पर अपने स्तर पर करवा सकेंगे। 2 लाख से अधिक के कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होंगे। अब नई व्यवस्था के तहत उपमंडल स्तर पर 2 लाख से 25 लाख तक के कार्य एसडीओ ही अप्रूव कर सकेगा और सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चेयरमैन इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। पहले कार्यों की अप्रूवल की फाइलें मुख्यालय स्तर तक आती थी, अब स्थानीय स्तर पर ही सब अप्रूवल मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है और उनके कार्य पूरे नहीं हुए है तथा जिन विधायकों को पांच करोड़ रुपए की पूरी राशि मिलना अभी बकाया है, ऐसे मामलों में वे स्वयं हस्तक्षेप कर अगले सत्र या 31 मार्च तक पूरा करवाएंगे।

निगम के जरिए अनुबंधित नौकरी

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर रोज़गार दिये जाने के मामलों में कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें मिलती थी। कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर प्रारंभ में एक साल के लिए रोजगार दिया जाता है, यह कच्ची नौकरी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती होने पर इन युवाओं को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि ये युवा नियमित भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया

राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। इसके तहत, युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें विदेशों में भेजने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक प्राइवेट लोगों द्वारा गलत तरीके से युवाओं को विदेशों में भेजा जाता है, फिर कबूतरबाजी के मामले सामने आते हैं। इसलिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि युवा इसका लाभ उठाकर विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढ सकें।

मुआवजा राशि बढ़ाई

जलभराव के कारण जिस जमीन पर फसल की बुआई नहीं हो पाई, उन किसानों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली 6 हजार रुपए प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति एकड़ किया है। लेकिन जो किसान ईंट-भट्ठा लगाने तथा किसी निर्माण कार्यों के लिए वाणिज्य लाभ हेतु अपने खेत की मिट्टी का उठान करवाते हैं और जलभराव होता है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। सीएम ने कहा कि ऐसे किसानों को मत्स्य पालन की ओर बढ़ना चाहिए। तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण बनाया है। अब तक 1762 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ है। 663 का कार्य पूरा भी हो चुका है।

रोगियों को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में डयूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ रोगों से पीडित रोगियों को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। बताया कि दुर्लभ रोगों की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत डयूकेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ रोगों से पीडित रोगीयों के उत्कृष्ट केंद्रों मे उपचार के लिए 50 लाख रुपये तक की वितीय सहायता प्रदान की जा रही हैं।

महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिह्नित

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न विषयों के पीजीटी पदों हेतु 3,863 पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकूला को पत्र भेजा गया है। इतना ही नहीं 7,471 टीजीटी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजने का मामला प्रक्रियाधीन है। इन पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी।

- संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप सी की 35 हजार और ग्रुप डी की 15 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

विकास कार्यों में तेज़ी लाने हेतु 'ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल' शुरू किया है जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार पर प्रहार

न कोई समझौता, न कोई भेदभाव

मनोज प्रभाकर

ईमानदार सरकार में 'तीन दो पांच' करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। अधिकारी हो या कर्मचारी, छोटा हो या बड़ा, हेराफेरी करते हुए पाया जाता है तो तुरंत नप जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति मनोहर सरकार का कोई समझौता नहीं है। गलत काम करने वालों को इस सरकार के किसी दरवाजे पर शरण भी नहीं मिलती। उनको तय प्रक्रिया के तहत अंजाम भुगतना होता है। काम के मामले में न कोई भाई भतीजा और न कोई रिश्तेदार।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब पहली बार मुख्यमंत्री की सीट संभाली थी, जीरो टोलरेंस का ऐलान कर दिया था। साफ कह दिया था 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' आठ बरस बीत गए। अनेक प्रकार की हवाएं चली लेकिन वे अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुए। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने बड़े बड़ों को भी नहीं बख्शा। उनके नेतृत्व में संबंधित एजेंसियां पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। बीते साल अनेक अधिकारी व कर्मचारियों को नकेल डाली गई।

पूरे साल उड़ता रहा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने का विज़न इस बात को दर्शाता है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा 1303 रेड/औचक निरीक्षण किये गये और 86,61,75,313 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

एक जनवरी, 2022 से 30 दिसंबर, 2022 तक विभिन्न जिलों में अलग-अलग सरकारी विभागों व प्राईवेट संस्थानों पर कुल 1303 रेड/औचक निरीक्षण किये गये। इस दौरान पाई गई अनियमिताओं के कारण कुल 456 मुकदमें अंकित करवाये गये, जिनमें 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 1303 रेड/औचक निरीक्षण में 94 सरकारी संस्थान तथा अन्य प्राईवेट संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में सी.एम.एफ.एस. को प्राप्त होने वाली शिकायतों/आसूचना पर की जाने वाली जांचों में 28 मुकदमें अलग से दर्ज करवाये गये हैं।

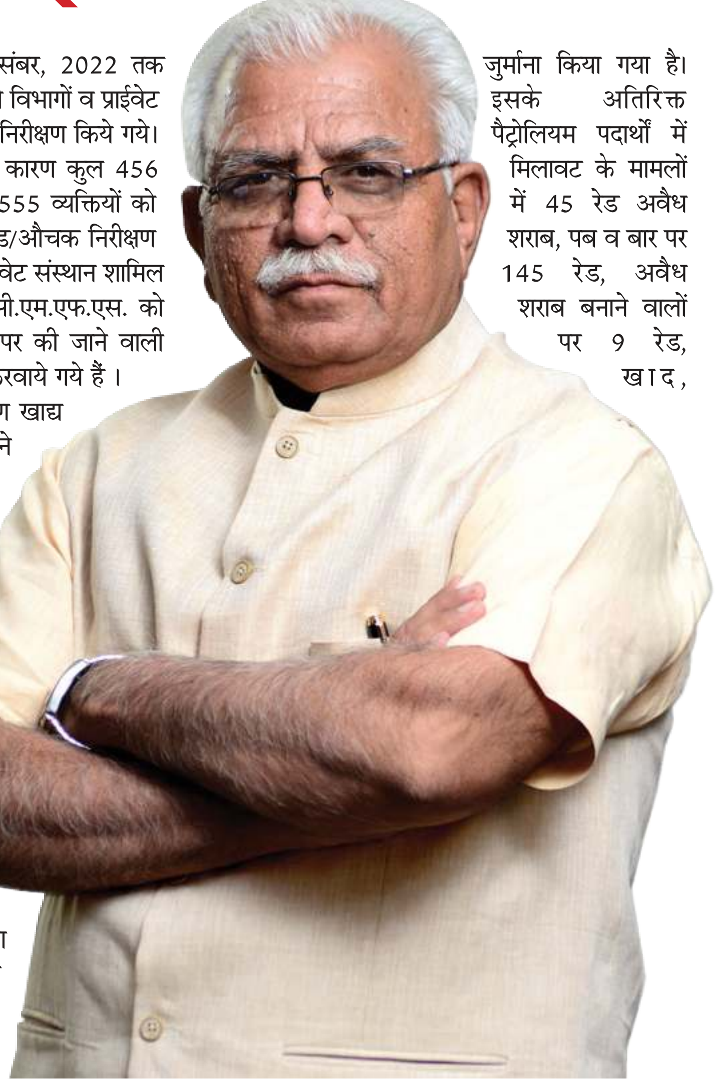

सबसे अधिक रेड/औचक निरीक्षण खाद्य पदार्थों की दुकानों व उनको तैयार करने वाले गोदामों पर कुल 313 रेड की गई तथा इनमें अनियमितता पाने पर 48 केस दर्ज किये गये व 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 2000 किलो ग्राम मिठाईयां अनसेफ पाए जाने पर नष्ट करवाया गया।

जीएसटी चोरी के आरोप में करोड़ों का जुर्माना

जीएसटी चोरी के मामले में कुल 55 रेड/औचक निरीक्षण के दौरान 1,32.78,112 रुपए का जुर्माना किया गया तथा माईनिंग मैटीरयल से सम्बन्धित ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए 68 रेड की गई, जिसमें 1,72,58,809 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट के मामलों में 45 रेड अवैध शराब, पब व बार पर 145 रेड, अवैध शराब बनाने वालों पर 9 रेड, खाद, बीज, कीटनाशक बेचने वालों पर 41 रेड, अवैध बोरवैल चलाने व बिजली चोरी पर 55 रेड, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में औचक चौकिंग 57, घरेलू गैस सिलेन्डरों की काला बाजारी करने वालों पर 50 रेड, नियमों की अवहेलना करके आर.एम.सी. प्लांट चलाने वालों पर 15 रेड की गई।

इस वर्ष और मजबूत होगी विजिलेंस ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्यूरो की विभिन्न पहलों को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को 'ट्रैप मनी' प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना भी शामिल है। इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं जिसमें 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना, सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव, छः डिविजनल सतर्कता ब्यूरो का सृजन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में वर्ष 2023-2024 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इनको काबू करने में मिली कामयाबी

एक जिला टाउन प्लानर को 5,00,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही सह आरोपी तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और एक जेल अधीक्षक को भी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा, वर्ष के दौरान पांच एचसीएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के दो मुख्य अभियंता, एक अधीक्षक अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता, एक मुख्य लेखा अधिकारी और एक संयुक्त निदेशक को सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम के एक अधीक्षक अभियंता एवं लेखापाल को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं सिंचाई विभाग के दो कार्यकारी अभियंता को 1,60,000 रिश्वत, बिजली विभाग के दो उपमंडल अभियंताओं एवं सह आरोपी को 3,00,000 रुपए लेते, खनन एवं भूविज्ञान का एक खनन अधिकारी को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग का एक भवन निरीक्षक को 5,00,000 रुपए लेते और आबकारी एवं कराधान विभाग के एक कराधान निरीक्षक को 2,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया।

इसी प्रकार 2 इंस्पेक्टर/एसएचओ, राजस्थान पुलिस के एक सेवानिवृत्त डीएसपी और करनाल में एमवीओ के रूप में कार्यरत एक अन्य इंस्पेक्टर सहित 46 पुलिस कर्मियों, राजस्व विभाग के 33 अधिकारी/कर्मचारियों, बिजली निगमों के 24, शहरी स्थानीय निकायों के 14, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के 5, परिवहन के 5, शिक्षा विभाग के 4, आबकारी व कराधान के 3, सहकारिता के 3, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के 3, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 3, बागवानी के 3, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के 3, स्वास्थ्य के 2, एचएसवीपी के 2, खनन और भूविज्ञान के 2, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के 2, सिंचाई के 2, वन के 2 और पशुपालन एवं डेयरी, रोजगार, मत्स्य पालन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गृह रक्षक, हाउसिंग बोर्ड, एचपीएचसी, उद्योग और वाणिज्य, श्रम निर्माण कल्याण, जेल, पंचायती राज, अभियोजन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कोषागार और लेखा तथा वक्फ बोर्ड जैसे 15 अन्य विभागों के कर्मचारियों को अलग-अलग मामलों में 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

काली कमाई से अर्जित संपत्ति होगी कुर्क: वर्ष 2023 में भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध कमाई की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के राज्य सरकार के अभियान को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को एक नई पहल के तहत 'सम्मान पत्र' से सम्मानित किया जा रहा है।

जांच को अंतिम रूप: 2022 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान के दौरान, ब्यूरो ने राज्य सरकार के निर्देश पर 22 राजपत्रित अधिकारियों, 23 अराजपत्रित अधिकारियों और 12 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 65 जांच दर्ज की हैं। वर्ष के दौरान, 90 जांच को अंतिम रूप दिया गया। 2022 के दौरान पूरी की गई 90 जांचों में से ब्यूरो ने 27 राजपत्रित अधिकारियों, 32 अराजपत्रित अधिकारियों और 23 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने, 20 जांचों में 36 राजपत्रित अधिकारियों, 8 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ 14 जांचो में विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। आठ जांचों में 5 राजपत्रित अधिकारियों, 14 अराजपत्रित अधिकारियों और एक व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए भी कहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां दें शिकायत

विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो ने नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और रिश्वतखोरी की शिकायतों को टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 और व्हाट्सएप नंबर 094178-91064 पर रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है।

विजिलेंस के निशाने पर रहे भ्रष्ट अधिकारी

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रदेश सरकार की जीरो-टोलरेंस नीति के अनुरूप गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए हैं, जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई है। ब्यूरो ने 2022 में 170 ट्रैप सहित 246 मामले दर्ज किए जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं।

वर्ष 2022 में 170 रेड की और मौके पर व तलाशी के दौरान 6,21,70,230 रुपए बरामद किए गए। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर-राजपत्रित अधिकारी और 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि 246 मामलों में से 170 केस रेड व ट्रैप में और 76 जांच व विशेष चेकिंग पर दर्ज किए गए। हर महीने औसतन 18 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि सतर्कता ब्यूरो ने अपना ध्यान क्लर्क, पटवारी, लाइनमैन, पुलिस कर्मियों आदि जैसे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों से वरिष्ठ रैंक पर स्थानांतरित किया, जो अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने में सरगना होते हैं। ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की छापेमारी और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के तहत सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की दिशा में क्लीन-अप कार्य के रूप में देखा जा रहा है।

हरियाणा के गांवों में हर घर शुद्ध व स्वच्छ जल पहुंचे, इसके लिए पेयजल सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है व ज़रूरत के अनुसार नए जलघरों का निर्माण भी करवाया जा रहा है।

प्रदेश की सभी पब्लिक लाइब्रेरियों की देखरेख का कार्य सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग को दिया गया है जिसके तहत पहले चरण में अंबाला, करनाल व गुरुग्राम की पब्लिक लाइब्रेरियों को आधुनिक किया जाएगा।

डिज़िटल कामकाज से मिली

विशेष प्रतिनिधि

प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में डिज़िटल प्रणाली का विशेष योगदान रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह पुराना सपना था कि साफ सुथरी व्यवस्था प्रदान करने के लिए कामकाज का ऑनलाइन होना अनिवार्य है। उनके मार्गदर्शन में संबंधित विभागों के अथक प्रयासों से यह संभव हो सका। सुशासन को मजबूती एवं गति देने वाले विभागों को मुख्यमंत्री ने शाबाशी दी और पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने इस दिशा में काम करने वाले विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए 'स्टेट लेवल अवार्डस' तथा 'स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस' शामिल हैं।

पुरस्कार पाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है।

परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को 6 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। पी.पी.पीनागरिकों को 'पेपरलेस' व 'फेसलेस' सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है। 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है।

ई-फसल क्षतिपूर्ति

सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई। रबी-2023 से पूरे राज्य में (फसल बीमा के मामले को छोड़कर) किसानों के लिए फसल नुकसान के आवेदन, सत्यापन, आकलन और मुआवजे हेतु यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यह प्रणाली केवल 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पर उपलब्ध है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में अनुबंध के आधार पर कर्मी प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एच.के.आर.एन.एल. ने परिनियोजित मैनपावर को लगभग 800 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके अलावा, 70,000 से अधिक परिनियोजित मैनपावर अब ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का लाभ उठा रही हैं, क्योंकि उनके प्रीमियम ऑनलाइन स्वचालित पे-रोल प्रणाली के माध्यम से जमा हो रहे हैं।

ऑटो अपील सिस्टम

ऑटो अपील सिस्टम सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 15 दिसंबर, 2022 तक 32 विभागों/संस्थाओं की 372 अधिसूचित सेवाएं ए.ए.एस. पर मौजूद हैं। प्रथम शिकायत निवारण अथॉरिटी, द्वितीय शिकायत निवारण अथॉरिटी और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपील की गई हैं, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है। एएएस के लॉन्च के साथ, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत कम हो गई है।

ई अधिगम

राज्य में व्यक्तिगत और अनुकूलनीय शिक्षण समर्थित टैबलेट आधारित शिक्षण कार्य म ई-अधिगम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई, 2022 को किया गया। यह कार्य म राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10-12 के सभी 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शुरू किया गया है। अब तक 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से 78 प्रतिशत को टैबलेट और डेटा सिम मिल गया है। सभी स्कूल प्रमुखों, टी.जी.टी. और वी.टी को टैबलेट और डेटा सिम प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले सभी अनिवार्य विषयों के लिए पीएएल को लागू करना है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना

अंत्योदय या अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के उद्देश्य के साथ हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 8 61 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं।

चिरायु हरियाणा

मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है। लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह 5 लाख रुपए तक के मुफ्त ईलाज का लाभ मिलेगा। चिरायु योजना के तहत अब तक 26 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

मोबाइल मेडिकल यूनिट

दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट की तर्ज पर 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट (47 नई . 12 मौजूदा) का बेड़ा तैनात किया है। एम.एम.यू. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच गांव का दौरा करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अक्तूबर, 2022 तक) 1.36 लाख से अधिक मरीजों को उनके घर द्वार पर सेवाएं दी जा चुकी हैं।

विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ई-नीलामी के माध्यम से अपनी संपत्ति की बि'ी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने डेढ़ साल की अल्पावधि के दौरान 20,000 से अधिक संपत्तियों को बेचकर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। एच.एस.वी.पी. ने समयबद्ध तरीके से भूमि भुगतान की अपनी बकाया राशि को चुकाने का भी फैसला किया है और किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है। एच.एस.वी.पी. ने वर्ष 2021-22 के दौरान 1900 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है और यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

फसल समूह विकास कार्यक्रम

राज्य में लगभग 400 बागवानी संभावित समूहों को मैप किया गया है तथा बागवानी समूहों सहित 683 एफ.पी.ओबनाए गए हैं। लगभग 16,817 मीट्रिक टन उपज के लेन-देन के लिए व्यापार और कृषि-व्यवसाय गतिविधियों के लिए 29 एफ.पी.ओ. और कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों के बीच 54 एम.ओ.यू. किए गए हैं। बागवानी क्षेत्र और उपज की पूरी मैपिंग की गई है। 33 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। इस कार्य म के लिए हरियाणा को बेस्ट स्टेट एग्री-बिजनेस अवार्ड मिला है।

फसल अवशेष प्रबंधन

यह परियोजना हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर केंद्रित है। पराली जलाने से राजस्व का नुकसान होता है और वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विभाग के सतत् प्रयासों से वर्ष 2018 से अब तक 702 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 3860 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू और इन-सीटू उपकरण सब्सिडी के रूप में लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

हरियाणा वक्फ बोर्ड के ईमामों के वेतन में लगभग 50 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि की गई है और हर साल पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय की एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन किया। यहां औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप तीन वर्षीय बीएससी एनिमेशन व मल्टीमीडिया का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

विकास को रफ़्तार

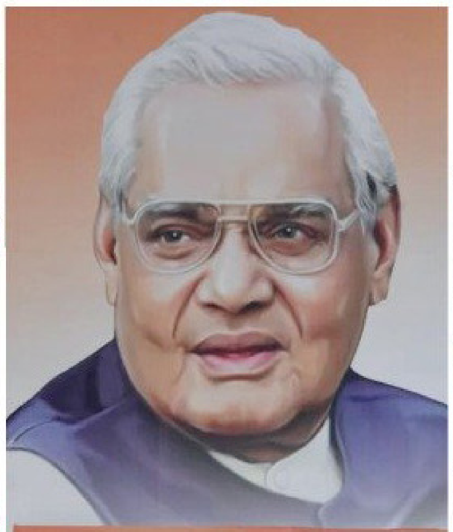

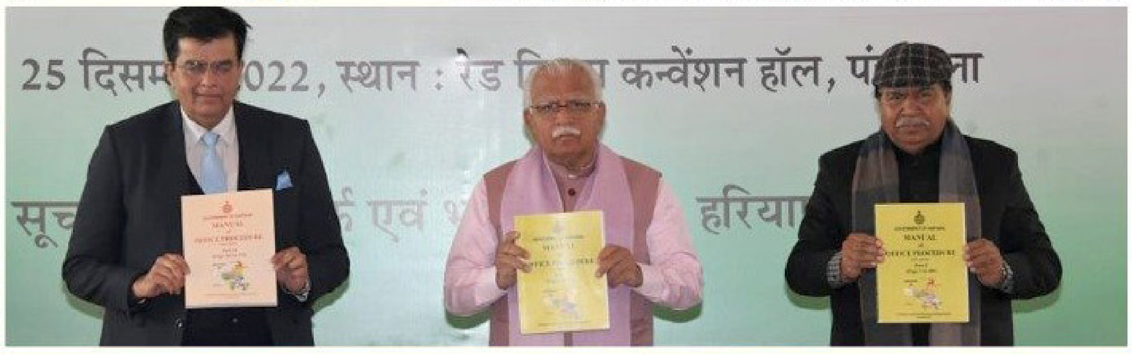

कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा गया। इससे स्थानीय पुलिस को नशा तस्करी सरगना व फाइनेंसर आदि को लक्षित करने में मदद मिली है, जो स्वयं नशीले पदार्थों की तस्करी में सीधे तौर पर शामिल न होकर पर्दे के पीछे काम करते हैं। अक्सर, स्थानीय पुलिस केवल छोटे ड्रग पेडलर्स को ही पकड़ पाती है, परन्तु मुख्य तस्कर, जो नशे के व्यापार को संचालित करते हैं, अक्सर सबूत की कमी के कारण छूट जाते हैं।

डिजिटल मीडिया

सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया अनुभाग बनाया गया है। डिजिटल मीडिया अनुभाग सरकार की नवीनतम योजनाओं एवं अधिसूचनाओं के विषय में जानकारी प्रभावी और प्रामाणिक माध्यम व त्वरित तरीके से लोगों तक समय पर पहुँचाता है। यह अनुभाग फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चैक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रति' या देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एनीमिया उन्मूलन सप्ताह

मई और नवंबर माह में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के दौरान 8.5 लाख से अधिक व्यक्तियों के एच.बी. स्तर का परीक्षण किया गया और लगभग 7.3 लाख व्यक्तियों की डिजिटल लाइन सूची को एनीमिया ट्रैकिंग वेब पोर्टल पर रखा गया है। 4.3 लाख से अधिक एनीमिक मरीजों का नि:शुल्क उपचार किया गया और लगभग 50 हजार गंभीर एनीमिक मरीजों को आगामी जांच के लिए उच्चतर केन्द्रों में भेजा गया।

पोर्टल से प्राप्त करें जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द

राज्य सरकार ने अधिकतम शासन व न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी सुशासन की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए हरियाणा में जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द (कॉपी) ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके तहत अब किसानों को जमाबंदी की फर्द माउस की एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल सकेगी।

सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन जमाबंदी प्रणाली सुशासन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।

अब जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए आम नागरिकों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होने के बाद अब माउस की एक क्लिक पर सारा रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राजस्व रिकार्ड को पहले देखने और ट्रेस करने में काफी समय लगता था। सारा रिकॉर्ड कपड़ों की गठड़ियों में बंधा होता था। कई बार पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन मॉडर्न रेवेन्यू रिकार्ड रूम से अब यह सुविधा लोगों को एक क्लिक पर तत्काल मिल रही है। तहसीलों में सभी काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पारदर्शी एवं दूरगामी सोच के चलते हरियाणा सरकार ने आईटी के माध्यम से प्रदेश की जनता को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन दिया है। अंत्योदय व सबका साथ-सबका विकास की भावना के अनुरूप विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने आईटी व डिजिटल माध्यम से सेवाओं का सरलीकरण किया है, जिससे सुशासन और अंत्योदय की भावना को बल मिला है।

क्या होती है जमाबंदी

यह हर राजस्व संपदा में रिकॉर्ड-ऑफ-राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया गया एक दस्तावेज है। इसमें स्वामित्व, खेती और भूमि में विभिन्न अधिकारों के अद्यतन के संबंध में प्रविष्टि शामिल हैं। जब पटवारी द्वारा जमाबंदी तैयार की जाती है और राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। संशोधित जमाबंदी की दो प्रतियां तैयार की जाती हैं। एक प्रति जिला अभिलेख कक्ष को प्रेषित की जाती है और दूसरी प्रति पटवारी के पास बंदोबस्त की अवधि के लिए रहती है। पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 44 के तहत जमाबंदी में प्रविष्टियों के साथ सत्य का अनुमान लगाया जाता है। अधिकारों के सभी परिवर्तन राजस्व अभिकरण के संज्ञान में आने वाली भूमि को राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमाबंदी में परिलक्षित किया जाता है।

अमृत सरोवर मिशन

अमृत सरोवर मिशन के तहत ग्रे वाटर मैनेजमेंट और बेहतर डिजाइन के साथ ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार और विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त, 2023 तक 2856 तालाबों का कार्य पूर्ण किया जाना है। 30 नवंबर, 2022 तक 615 तालाबों का कार्य पूरा किया जा चुका है। 830 तालाबों का कार्य प्रगति पर है।

रैनी वेल योजना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हाल ही में 184.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पलवल जिले के पृथला व पलवल ब्लॉक और फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों को कवर करने वाली एक रेनी वेल आधारित परियोजना शुरू की है। इससे 15 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 3,06,814 (2031) की संभावित आबादी को लाभ होगा। पूर्व में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन सतनाली समूह के 25 गांवों के लिए विशिष्ट परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से 99,962 व्यक्तियों की संभावित आबादी को लाभ होगा।

कार्य एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने उद्योग एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल विकसित किया है, जो बहुत ही कम अवधि में कक्षा 9वीं से डॉक्टरेट स्तर तक कार्य एकीकृत कौशल और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। व्यवसायिक उच्चतर शिक्षा का यह उद्योग-एकीकृत मॉडल कौशल आधारित शिक्षा के बारे में हरियाणा में लोगों की मानसिकता को बदलने और इसे उनके लिए आकांक्षी बनाने में सहायक बन गया है। अधिकांश पाठ्य' मों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के दौरान, विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए प्रतिमाह तक वजीफा प्रदान किया जा रहा है।

हार्ड-कोर ड्रग तस्करों पर लगाम

अधिनियम के अनुपालन में बंदियों को

प्रदेश सरकार सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने व गन्ना उत्पादक किसानों के उत्थान के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो चीनी मिलों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेगी।

हरियाणा राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री को रोज़गार के उद्देश्यों के लिए किसी अन्य तीन वर्षीय स्नातक डिग्री के समकक्ष माना जाएगा।

नई तकनीक से बढ़ रही किसानों की आय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विगत आठ वर्षों से प्रदेश सरकार किसान व किसानी के प्रति गंभीर है और केंद्र सरकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हर योजना को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले मूर्तरूप दे रही है। किसानों का रुझान पारंपरिक खेती के साथ-साथ अन्य नकदी फसलों की ओर बढ़े, इसके लिए न केवल केंद्र सरकार के बल्कि दूसरे देशों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र खोल रही है, जिसके तहत किसानों को बागवानी व मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई-नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है और किसान इन्हें अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं किसानी से जुड़े रहे हैं व किसानों की दुःख-तकलीफ़ से भली-भांति परिचित हैं। किसान ज़मीन के साथ-साथ अपनी संतान को पानी भी विरासत में देकर जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक अनूठी पहल करते हुए 'मेरा पानी, मेरी विरासत' नाम से एक नई योजना आरंभ की, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश का किसान आज नई तकनीक का उपयोग कर कम लागत में अधिक मुनाफ़ा कमा रहा है। आज हमारे सामने प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण है।

हरियाणा के दो प्रगतिशील किसानों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें सोनीपत जिले के कंवल सिंह चौहान व करनाल जिले के सुलतान सिंह शामिल हैं। इन दोनों किसानों को परंपरागत खेती से हटकर स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न तथा मत्स्य पालन में उत्कृष्टता के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने एक और अनूठी पहल करते हुए जो प्रगतिशील किसान कम से कम दस और किसानों को प्रगतिशील किसान बनने के लिए प्रेरित करेगा उसे किसान श्री पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है।

आधुनिक तकनीक को बढ़ावा

प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 11 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। इन उत्कृष्टता केंद्रों से अनेकों किसानों को जोड़ा गया है इसके अलावा, 'विलेज ऑफ एक्सीलेंस' के माध्यम से भी बेहतर कृषि, बागवानी व पशुपालन में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज़ करने वाले गावों को चिह्नित किया गया है। किसान उत्पादक समूह सीधे बाजार से जुड़े हैं। 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के तहत बागवानी फसलों का 40 हजार रुपए प्रति एकड़ बीमा किया जाता है। राज्य में बागवानी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। राज्य के किसानों का रुझान परंपरागत खेती की जगह बागवानी की ओर हो रहा है। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे नए शोध और विकसित की जा रही तकनीकों का लाभ किसानों को सीधे मिल रहा है।

पैक हाउस से बदली किसानों की तकदीर

किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ कृषि उत्पादों की धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम आसानी से हो, इसके लिए सरकार पैक हाउस स्थापित करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों की खेती को अधिक बढ़ावा देने व आय बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

बेस्ट स्टेट का पुरस्कार

कृषि क्षेत्र में नीतियां बनाने, उत्पादन, प्रौद्योगिकी, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद् द्वारा इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड-2022 में हरियाणा को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार भी दिया जा चुका है।

गन्नौर में होगी एशिया की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मार्केट

सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मार्केट बनाने जा रही है। इसके बनने से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकेंगे। हरियाणा का किसान अनाज के साथ-साथ फल, सब्जियां और फूल की खेती करके देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान कर रहा है। आज हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश के स्तर पर उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लगभग 5 करोड़ की आबादी की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में आगे आ रहा है।

जैविक मल्चिंग से आलू की खेती

एक साल तक आलू सुरक्षित, कॉल्ड स्टोर की ज़रूरत नहीं

संगीता शर्मा

भारत में वर्ष-2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं इसकी पहल हरियाणा में भी शुरू हो गई। बाजरा की खेती करने वाले रेवाड़ी के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार बाजरा के फसल अवशेष से आलू को जैविक मल्चिंग तकनीक से उगाकर मुनाफ़ा कमा रहे हैं। मल्चिंग तकनीक से खरपतवार नियंत्रण, लागत कम, पानी की बचत और पैदावार अधिक होती है। इस आलू को कोल्ड स्टोर के बिना एक साल तक छाया में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि में बेड को बाजरे, धान की पराली के अवशेष और प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है। यह तकनीक फसल अवशेष को खेती में प्रयोग करके न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है साथ ही लोगों को बिमारियों से ग्रस्त होने से राहत प्रदान करती है।

जैविक आलू मल्चिंग तकनीक से

सुनील कुमार का कहना है कि इस तकनीक से जैविक आलू उगाने से किसान को बहुत फ़ायदे हैं और कीमत भी अधिक मिलती है। सुनील ने बताया कि आधे एकड़ ज़मीन में आलू की जैविक खेती की और पैदावार 32 क्विंटल हुई। 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब के बिक रहा है और खरीददार खेत व घर से ही खरीदकर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस खेती से एक तो किसान को आलू बिजाई के लिए मशीन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इससे 2,000 से 3,000 रुपए की बचत होती है। खेत में बिना बिजाई के आलू को छिड़क दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वैसे तो मल्चिंग में फसल अवशेष धान की पराली से बीज को ढक सकते हैं, लेकिन वह बाजरे की खेती करते हैं तो उन्होंने बाजरे के फसल अवशेष से आलू को ढक दिया। ढकने से खरपतवार पैदा नहीं हुई और पेस्टीसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ा। इस खेती से पानी की बचत होती है। इसके ढकने के बाद पानी में नमी रहती है तो पानी की बचत होती है। इसमें निराई-गुड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो लेबर से करवाना पड़ता है वह बहुत महंगा होता है। इसमें खुदाई के समय मशीन का प्रयोग नहीं करना पड़ता। फसल अवशेष हटाते ही आलू निकल जाते हैं। उन्होंने बताया कि जैविक आलू उगाए हैं और इस तकनीक से पैदावार भी ज्यादा आएगी। सुनील ने बताया कि आलू उच्चतम दर्ज़े के पैदा हुए हैं जिसे कोल्ड स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे एक साल तक छाया में रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। वह कहते है कि कोल्ड स्टोर नजदीक न होने के कारण और खर्चा अधिक आने से कई किसान आलू की खेती करने से कतराते थे, लेकिन अब इस तकनीक से आलू की खेती करके किसान मुनाफ़ा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से आलू उगाने में अंकुरण व फुटाव शत-प्रतिशत होता है, जबकि अन्य तकनीक से 80 प्रतिशत फुटाव होता है। आलू का आकार व भार अधिक होता है। खर्चा नाममात्र ही होता है।

हरियाणा बागवानी विभाग किसानों को नई-नई तकनीक के प्रयोग के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। राज्य में नई तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और हाई-टेक संरक्षित संरचनाओं के लिए किसानों और उद्यमियों को 35 प्रतिशत सहायता के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल प्लास्टिक और वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी के तहत 10,000 एकड़ कवर करने का लक्ष्य है। हरियाणा आलू के बीज उत्पादन का नया केंद्र बनता जा रहा है। आलू के प्रजनक और प्रमाणित बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़, करनाल में हैं।

मल्चिंग खेती के फ़ायदे

- मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है।
- मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं होने पाता है।
- पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
- खेत में मिट्टी के कटाव नहीं होता है।
- खरपतवार से बचाव होता है।
- पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।
- मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है।
- पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह होता है।

नोट: मल्चिंग दो प्रकार की होती है। पहली जैविक मल्चिंग व दूसरी प्लास्टिक मल्चिंग।

जैविक मल्चिंग में पराली, पत्तों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इसे प्राकृतिक मल्चिंग भी कहा जाता है। यह बहुत ही सस्ती होती है। इसका उपयोग प्रायः जीरो बजट खेती में भी किया जाता है। इसलिए किसानों को पराली को न जलाकर इसका उपयोग मल्चिंग में करना चाहिए। मलचिंग के उपयोग से आपको पराली की समस्या से निजात मिलेगा और उपज भी अधिक मिलेगी।

प्लास्टिक मल्चिंग बाज़ार में मिलते हैं। यह जैविक मलचिंग की तुलना में खर्चीली होती है। लेकिन पौधों को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है।

हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।

वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक या संस्था अपनी उपलब्धियों के विवरण व प्रमाण पत्रों के साथ विभाग के पोर्टल award.socialjusticehry.gov.in पर 7 फरवरी, 2023 तक अपना आवेदन कर सकते हैं।

आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की

संवाद ब्यूरो

प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान में 'आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से आह्वान किया कि वे गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहें ताकि वे लोग भी मुख्यधारा में आ सकें।

इस अवसर पर समाज में बदलाव का संदेश देते हुए मनोहर लाल ने कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि 'चलो जलाएं दीप वहां, जहां अंधेरा हो घना' अर्थात सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उसके जीवन से दुख, दर्द व दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले 8 वर्षों से अंत्योदय के मूलमंत्र पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के कार्य को अंजाम दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों व फ्लैगशिप प्रोग्रामों को अन्य राज्यों ने भी अपनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दादी प्रकाशमणी पार्क के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए। अलग-अलग भाषाओं में महापुरुषों की शिक्षाएं रही हैं, परंतु सभी संतों का मूलभाव यही है कि किस प्रकार से समाज में सुधार लाया जाए। ऐसे सभी संतो-महापुरुषों की शिक्षाओं को जन-जन

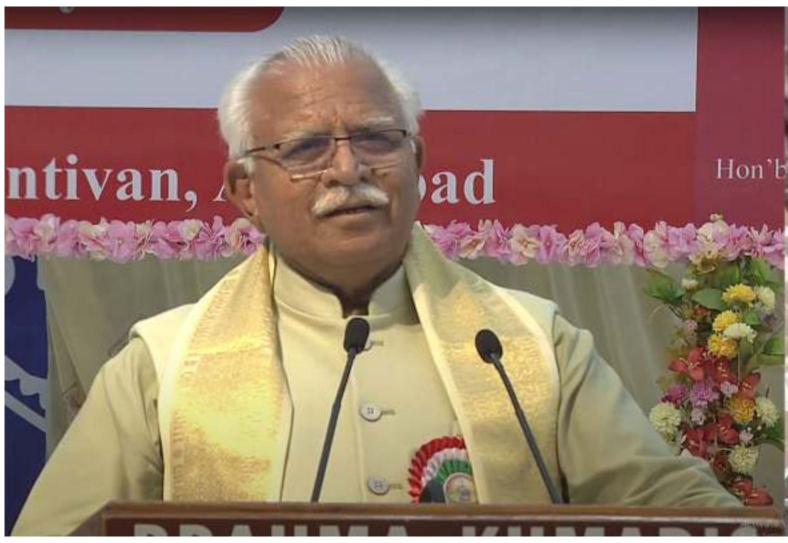

तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने संत-महापुरूष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है, जिसके तहत सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। सरकार की यह एक अनूठी पहल है, ताकि आज की युवा पीढ़ी को भी पता लगे कि किस प्रकार से महापुरुषों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज को आधुनिकता की ओर पहुंचाया है। इतना ही नहीं, यह योजना समाज में भाईचारा व सद्भावना को बढ़ाने का भी माध्यम बन रही है।

मनोहर लाल ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज संगठन का लक्ष्य भी समाज सुधार के साथ-साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना है। सरकारें विकास कार्य करती हैं, जिसे भौतिक विकास की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सरकारों का काम केवल भौतिक विकास ही नहीं बल्कि समाज में शिक्षा के जरिए आध्यात्मिक विकास करना भी होना चाहिए।

आशावादी बनें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे प्रदेश की लगभग पौने 3 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम ही हमारा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को मानते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज सुधार के कार्य करते हुए कठिनाईयां बहुत आती हैं, परंतु हमें निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि आशावादी बनकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है', इस मूल वाक्य पर चलते हुए जीवन में आने वाली सभी बुराइयों के अंधेरों को दूर कर निरंतर समाज हित में कार्य करते रहना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रादेवी मंदिर से आदिबद्री तक रोप-वे बनाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही, शिवालिक हिल्स के कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें छोटा त्रिलोकपुर, आदिबद्री, लोहगढ़, कपालमोचन, कलेसर इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग बनाने की संभावना तलाशी जाएगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग शुरु करने की भी योजना है। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख राज की पहली राजधानी लोहगढ़, यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य एवं बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए स्मारक की आधारशिला रखने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

सरस मेले में जुटे हस्तशिल्प के कद्रदान

हरियाणा में हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। मेले व प्रदर्शनियां हस्तशिल्पियों को आर्थिक तौर से मज़बूत करने में सफल साबित हो रहे हैं। इसका सार्थक परिणाम हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंतराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव-2022 में ब्रह्मसरोवर के तट पर आयोजित सरस मेले में देखने को मिला। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सरस मेला 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। ब्रह्मसरोवर के तट पर आयोजित इस सरस मेला में पूरे भारत वर्ष के 20 राज्यों से आये स्वयं सहायता समूहों के 130 हस्तशिल्पियों/दस्तकारों द्वारा अपने तैयार किये हुये उत्पादों की प्रदर्शनी की स्टाल लगाई गई व अपने उत्पाद बेचे गये। सभी स्वयं सहायता समूहों द्वारा कुल 1,37,19,-520 रुपए की बिक्री की गई। जिसमें से हरियाणा राज्य के हस्तशिल्पियों की बिक्री 64,52,370 रुपए व अन्य राज्यों (हरियाणा को छोड़कर) के हस्तशिल्पियों ने पूरे मेले के दौरान 72,67,150 रुपए की बिक्री की गई।

हरियाणा ने 68 स्टॉलों में भाग लिया

इस सरस मेला में भाग लेने वाले सभी स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्पी/दस्तकार काफ़ी उत्साहित थे। इस मेले में दौरा करने आये स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी अपना रोज़गार स्थापित करने की प्रेरणा मिली। सरस मेला में विभिन्न राज्यों से भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्पकारों/दस्तकारों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है। आंध्र प्रदेश ने एक, असम ने चार, बिहार ने दो, दिल्ली ने छह, गुजरात ने दो, हिमाचल प्रदेश ने सात, जम्मू एंड कश्मीर ने तीन, झारखंड ने एक,मध्य प्रदेश ने दो, महाराष्ट्र ने तीन, पंजाब ने चार, राजस्थान ने दो, सिक्किम ने एक, तमिलनाडु ने दो, तेलंगाना ने एक, त्रिपुरा ने तीन, उत्तर प्रदेश ने नौ, उत्तराखंड ने छह, पश्चिम बंगाल ने तीन और हरियाणा ने 68 स्टॉलों में हस्तशिल्पियों ने अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया। मेले में कुल 130 स्टॉल लगाई गई।

क्राफ्ट को मिली नई पहचान

हरियाणा के पंचकूला जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आचार, मुर्रब्बे आदि प्रदर्शित किये। इसी तरह भिवानी से आयी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोहे के बर्तनों का स्टाल लगाया तथा उनके उत्पाद पूरे मेले के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। पलवल से समूह की महिलाओं ने मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित किये। ऐसे ही अन्य जिलों से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर सरस मेले में भाग लिया। नीरज, जिला झज्जर ब्लॉक बहादुरगढ़ से, जो कि लकड़ी की नक्काशी का कार्य करते है, उन्होंने पहली बार सरस मेले में भाग लिया। नीरज अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी सम्मान प्राप्त कर चुके है। उनका कहना है कि मेले में क्राफ्ट को नई पहचान मिलती है और उत्पाद की बिक्री होने से मुनाफ़ा होता है। उदित नारायण ख़राब सामान से चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने भी इस सरस मेले में भाग लिया तथा अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हरियाणा में लगने वाले मेले से हस्तशिल्प को मार्केट की सुविधा मिलती है और क्राफ्ट की बिक्री हो जाती है। इसी तरह अन्य राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर से काहवा तथा ऊनी कपड़ें, मध्य प्रदेश से जड़ी-बूटी तथा जैविक उत्पाद, पंजाब से फुलकारी, हिमाचल प्रदेश से ऊनी उत्पाद, जड़ी-बुटियां तथा फुटवियर इत्यादि, उत्तराखंड से जैविक उत्पाद, उत्तर प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, बिहार से सिल्क के कपड़े आदि उत्पाद पूरे मेले के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। ये कारीगर अपने इन उत्पादों के माध्यम से अपने राज्यों तथा उनकी विभिन्न संस्कृतियों को प्रदर्शित करने में सफल रहे।

–संगीता शर्मा

हरियाणा सरकार ने यमुना एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें हरियाणा के उन सभी 11 नालों में प्रदूषण के नियंत्रण की परिकल्पना की गई है, जिनसे नदी में उपचारित या अनुपचारित जल गिरता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी है बशर्ते कि इसमें 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस

छब्बीस जनवरी का दिन हमारे लिए ख़ास महत्त्व रखता है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था इस दिन को राष्ट्रीय पर्व का दर्ज़ा प्राप्त है। प्रतिवर्ष इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

इंडिया गेट पर राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी, 2023 को भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई गणमान्य व प्रतिष्ठित शख्सियतें इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी।

भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर, 1946 से शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 2 साल, 11 माह, 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। भारत 26 जनवरी 1950 को 10:18 बजे गणराज्य बना और करीब छह मिनट बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में गणराज्य के पहले राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की।

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की आजादी थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देशभर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्त्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 444 अनुच्छेद 22 भागों व 12 अनुसूचियों में बांटा गया था। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है जबकि पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई। 'जन गण मन' को संविधान सभा ने 24 जनवरी,1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।

संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं जिसमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) सबसे प्रमुख और महत्त्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।

पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रतियां

भारतीय संविधान की दो प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई। भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाऊस में 26 जनवरी, 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धाजंलि देते हैं, जिन्होंने देश के आजादी में बलिदान दिया।

गणतंत्र दिवस समारोह

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस अवसर के महत्त्व को चिह्नित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय केडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं, समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति (सैनिकों के लिए एक स्मारक) जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है पर पुष्प माला डालते हैं, इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनट मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री, अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं, राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती हैं, प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है।

प्राची से झांक रही ऊषा

प्राची से झांक रही ऊषा,
कुंकुम-केशर का थाल लिये।
हैं सजी खड़ी विटपावलियां,
सुरभित सुमनों की माल लिये।

गंगा-यमुना की लहरों में,
है स्वागत का संगीत नया।
गूंजा विहगों के कण्ठों में,
है स्वतन्त्रता का गीत नया।

प्रहरी नगराज विहंसता है,
गौरव से उन्नत भाल किये।
फहराता दिव्य तिरंगा है,
आदर्श विजय-सन्देश लिये।

गणतन्त्र-आगमन में सबने,
मिल कर स्वागत की ठानी है।
जड़-चेतन की क्या कहें स्वयं,
कर रही प्रकृति अगवानी है।

कितने कष्टों के बाद हमें,
यह आज़ादी का हर्ष मिला।
सदियों से पिछड़े भारत को,
अपना खोया उत्कर्ष मिला।

धरती अपनी नभ है अपना,
अब औरों का अधिकार नहीं।
परतन्त्र बता कर अपमानित,
कर सकता अब संसार नहीं।

क्या दिये असंख्यों ही हमने,
इसके हित हैं बलिदान नहीं।
फिर अपनी प्यारी सत्ता पर,
क्यों हो हमको अभिमान नहीं।

पर आज़ादी पाने से ही,
बन गया हमारा काम नहीं।
निज कर्त्तव्यों को भूल अभी,
हम ले सकते विश्राम नहीं।

प्राणों के बदले मिली जो कि,
करना है उसका त्राण हमें।
जर्जरित राष्ट्र का मिल कर फिर,
करना है नव-निर्माण हमें।

इसलिये देश के नवयुवको!
आओ कुछ कर दिखलायें हम।
जो पंथ अभी अवशिष्ट उसी,
पर आगे पैर बढ़ायें हम।

भुजबल के विपुल परिश्रम से,
निज देश-दीनता दूर करें।
उपजा अवनी से रत्न-राशि,
फिर रिक्त-कोष भरपूर करें।

दें तोड़ विषमता के बन्धन,
मुखरित समता का राग रहे।
मानव-मानव में भेद नहीं,
सबका सबसे अनुराग रहे,

कोई न बड़ा-छोटा जग में,
सबको अधिकार समान मिले।
सबको मानवता के नाते,
जगतीतल में सम्मान मिले।

विज्ञान-कला कौशल का हम,
सब मिलकर पूर्ण विकास करें।
हो दूर अविद्या-अन्धकार,
विद्या का प्रबल प्रकाश करें।

हर घड़ी ध्यान बस रहे यही,
अधरों पर भी यह गान रहे।
जय रहे सदा भारत मां की,
दुनिया में ऊंची शान रहे।

महावीर प्रसाद 'मधुप'

उत्साह एवं उमंग का पर्व वसंत पंचमी

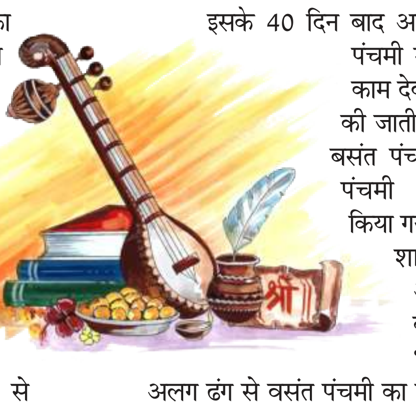

वसन्त पंचमी उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। बहुत से लोग इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते है। वसंत पंचमी को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है, जो वसंत के आगमन की प्रारंभिक तैयारियों को चिह्नित करता है। जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। यह त्योहार माघ महीने की शुक्ल पंचमी के दिन, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाएगा।

देवी सरस्वती को विद्य की देवी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि प्राचीनकाल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिवस माना जाता है। वसंत पंचमी त्योहार, देवी सरस्वती को समर्पित त्योहार है, जो ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी हैं। इस त्योहार पर महिलायें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, और पीले रंग के व्यंजन बनाती हैं। भारत में पूरे साल को छह मौसमों में बांटा जाता है जिसमें से वसंत सबका प्रिय मौसम होता है। इस महीने में, खेत सरसों के पीले रंग के फूलों से भर जाता है।

वसंत पंचमी को होली के त्योहार की तैयारी का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। वसंत पंचमी में विष्णु और काम देव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों-शास्त्रों तथा अनेक काव्यग्रंथों में भी अलग-अलग ढंग से वसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान भी ज्ञान के दीप जलाता है।

इस दिन लोग अपने घरों में पील रंग के व्यंजन बनाते है, कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं।

सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसन्त पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है-

**प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजिनीवती
धीनामणित्र्यवतु।**

अर्थात ये परम चेतना हैं। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हममें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है।

ये तो हुआ वसंत पंचमी का आध्यात्मिक पक्ष। अब अगर इसका प्राकृतिक पक्ष जान लिया जाए तो विषय कुछ और अग्रसर एवं सार्थक होगा। इन दिनों समस्त प्रकृति सर्द ऋतु के आवरण से बाहर आ रही होती है। मौसम में हल्की गर्माहट आने से पेड़ पौधों में कुछ नयापन आने की आतुरता होती है। नई कौंपलें दिखाई देती हैं और कोर आने लगता है। हवाओं में भी कुछ नई रवानगी को महसूस किया जाता है तो मानव देह में भी उत्साह महसूस किया जाता है। इसी उत्साह के चलते देश के कई हिस्सों में वसंत का भंगड़ा अथवा नृत्य समारोह आयोजित किए जाते हैं।

वसंत पंचमी कथा

मान्यता है कि प्रारंभिक काल में, भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्य की रचना की थी। परन्तु ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नही थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की, तब विष्णु से उनके समक्ष प्रकट हुए। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी परन्तु विष्णु जी के पास उनकी समस्या का हल नहीं था। इसलिए दोनों ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आव्हान किया। तब दुर्गा माता प्रकट हुई और उनकी समस्या के हल के लिए अपने शरीर में से देवी सरस्वती को प्रकट किया। तभी से, सभी जीवों को वाणी प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी सरस्वती का जन्म हुआ।

– संवाद ब्यूरो

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com